small arms survey

विषय विवरण

अंक 4 ■ जनवरी 2014

भारत में छोटे हथियार

अधिप्राप्ति और उत्पादन की एक सदी

परिचय

भारत सरकार द्वारा छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति देश की राष्ट्रीय सैन्य अधिप्राप्ति व्यवस्था को परिलक्षित करती है, जिसके तहत स्वदेशी हथियारों के उत्पादन और अधिप्राप्ति पर ज़ोर डाला जाता रहा है। इस गंभीर प्राथमिकता ने एक ऐसी राष्ट्रीय सैन्य नीति को जन्म दिया जिसे निष्क्रियता, कूटनीतिक दिशा के अभाव और सेना को ऐसे हथियार मुहैया कराने के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा जिसकी न ज़रूरत थी, न सैन्य ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें तैयार किया गया था। 90 के दशक में आलोचकों ने 'रक्षा उत्पादन की असफलता' पर खुलकर लिखना शुरू कर दिया था (स्मिथ, 1994, पृ. 222)। बाद में विश्लेषण के दौरान पाया गया कि भारत की 'रक्षा अधिप्राप्ति प्रणाली' एक किस्म की दुष्क्रिया (डिस्फंक्शन) की स्थिति में है और सेना उत्पादन को ख़ासतौर पर कमज़ोर बताया गया (कोहेन एंड दासगुप्ता, 2010, पृ. 143)।

इस बड़ी अधिप्राप्ति प्रणाली के तहत रूढ़िवाद और घरेलू उत्पादकों को तरजीह दी गई और घरेलू हथियारों के तकनीकी तौर पर निराशाजनक होने के बावजूद भारत की सेना और पुलिस के लिए छोटे हथियारों के आधुनिकीकरण को पीछे धकेल दिया गया। छोटे हथियारों के विकास का मुद्दा भारत की सुरक्षा नीति में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन 80 और 90 के दशक में तो ये मुद्दा सार्वजनिक चर्चाओं से भी गायब होने लगा। बल्कि, भारतीय सुरक्षा के आधुनिकीकरण में पारंपरिक और परमाणु हथियारों पर ज़ोर दिया जाने लगा (बेदी, 1999; गुप्ता, 1990)। इस तरह भारत में छोटे हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री ने धीरे–धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डिज़ाइन और नीतियों से पूरी तरह कटने लगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े छोटे हथियारों के उत्पादकों में से एक था, लेकिन फिर भी उसे नज़रअंदाज़ किया जाता रहा क्योंकि भारतीय कंपनियां घरेलू सैन्य ज़रूरतों और कानूनी एजेंसियों की ज़रूरतें पूरी करने में लगी रहीं। निर्यात बाज़ार पर उनका ध्यान कम ही था।

जैसा कि इस विषय विवरण में दिखाया गया है, 90 के दशक से ये चलन बदला है लेकिन अभी भी पुरानी धरोहर अगले कई दशकों तक भारत के आधिकारिक छोटे हथियारों की अभिप्राप्ति पर असर डालती रहेगी। इस विषय विवरण के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों, राज्यों और शहरों में 1990 के दशक से छोटे हथियारों की अभिप्राप्ति का विकेन्द्रीकरण, जिसकी वजह से कई आधिकारिक छोटे हथियारों के सप्लायरों का विविधीकरण हुआ है।
- भारत की राज्य सरकारों और सरकारी

मुंबई पुलिस कॉन्स्टेबल्स ली–एन्फील्ड राइफल्स के साथ। ली–एन्फील्ड राइफलें तकरीबन सौ सालों से भारतीय सेना और पुलिस का प्रमुख हथियार बनी हुई हैं, और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अभी भी प्रयोग में हैं। मुंबई, दिसंबर 2008. © सज्जाद हुसैन/एएफपी फोटो

एजेंसियों ने अपने लिए छोटे हथियारों की अभिप्राप्ति का विविधीकरण किया है, जिससे उनके हथियार आधुनिक तो हुए हैं लेकिन एक समान नहीं हैं।

- भारत में छोटे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास को अभी भी प्रकाशित किया जाना है। नतीजतन, कुल उत्पादन और आधिकारिक इन्वेंट्री आंकड़ों का सिर्फ आंकलन ही किया जा सकता है।

- कुल आधिकारिक भारतीय इन्वेंट्री के हिसाब से भारत में कुल 56 करोड़ छोटे हथियार हैं। इनमें से 26 करोड़ सेना के पास, 13 करोड़ अर्धसैनिक बलों के पास और 17 करोड़ पुलिस के पास हैं।

- इस रिसर्च के दौरान छोटे हथियारों को नष्ट करने का कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

- ली–एन्फील्ड राइफल अगले कई सालों तक भारतीय हथियारों में अग्रणी रहेगी। फिलहाल इसकी 19 करोड़ बंदूकें सर्विस में हैं।

- 2008 मुंबई हमलों के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने घरेलू हथियारों के उत्पादन पर पूरी तरह निर्भर होना कम कर दिया है, और आयात के ज़रिए आधुनिकीकरण कर रही है।

- अगर पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जाए तो भारतीय सेना, अर्धसेना और पुलिस को 60 करोड़ नए हथियारों की ज़रूरत होगी।

- घरेलू हथियारों के उत्पादन में एकाधिकार की वजह से भारत के छोटे हथियारों की इंडस्ट्री आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन आधिकारिक तौर पर विदेशी सप्लायरों से हथियारों के खरीदने के बढ़ते चलन की वजह से राष्ट्रीय इंडस्ट्री अब अपनी चमक खो रही है।

ये विषय विवरण भारत के छोटे हथियारों को दो दृष्टिकोणों से देखता है। पहला, ये सर्विस में मौजूद मुख्य हथियारों की पड़ताल करता है और अधिप्राप्ति, प्रोडक्शन और आयात के तीनों पहलुओं के इतिहास पर नज़र डालता है। दूसरा, ये हथियारों की एजेंसियों के कुल आकार की पड़ताल करता है। आंकड़ों और अनुमानों पर आधारित ये रिसर्च हथियारों के मुख्य प्रकारों की एक अनुमानित तस्वीर पेश करती है, और भारत में छोटे हथियारों के कुल आकार का अनुमान देती है। ये विषय विवरण हथियारों पर नज़र डालता है, जिसके आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं, और हेवी मशीनगनों, मोर्टारों और रॉकेटों जैसे हथियारों की बात नहीं करता जिनके बारे में दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।

इस विषय विवरण में दर्शाया गया है कि नवंबर 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत में छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति में रूढ़ीवादी होने के क्या नतीजे हुए। 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद 2008 में हुए हमलों की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में हथियारों के आधुनिकीकरण की दौड़ शुरू हो गई। आधिकारिक रूप में छोटे हथियारों की नीतियां भारतीय लोकतंत्र के और तत्वों से मिलती–जुलती है, जहां शक्ति केन्द्र सरकार के अलावा अन्य अर्धस्वायत्त एजेंसियों, जैसे राज्यों और नगर निगमों में बिखरी हुई है। छोटे हथियारों की राष्ट्रीय अधिप्राप्ति की जगह भारतीय राज्यों और एजेंसियों की अलग–अलग नीतियां हैं जिनकी वजह से कई बार पुराने घरेलू हथियार खरीद लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसी डिज़ाइनें आयातित कर ली जाती हैं जो बहुत आधुनिक और एडवांस्ड होती हैं। इसकी वजह से नए–पुराने हथियारों के मॉडलों का बेमेल सम्मिश्रण सुरक्षा एजेंसियों के पास दिखाई देता है।

भारत में छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति के तीन चरण

सरकारी सुरक्षा एजेंसियों – सेना, अर्धसेना और पुलिस – की छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति तीन चरणों में हुई है, जिन्हें अधिप्राप्तियों की रणनीतियों और हथियारों के प्रकारों के आधार पर बांटा जा सकता है:

- 1900 से 1963 में हथियार पुराने ब्रिटिश डिज़ाइन के बने होते थे, और उन्हें भारतीय ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां बनाया करती थीं। इस युग को छोटे हथियारों की बनावट में दिखाई देने वाली एकरूपता के आधार पर जाना जाता है। सभी एजेंसियों के पास एक से हथियार होते थे और सभी एक ही सप्लायरों के पास से आते थे। तब छोटे हथियारों में ली–एन्फील्ड राइफल और वेबले रिवॉल्वर चलन में थे।

- 1964 से 2007 में भारत–चीन युद्ध के बाद भारत ने सेमी–ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक हथियारों को बड़ी संख्या में अधिगृहित करना शुरू किया, और इसके लिए वे ज्यादातर विदेशी मॉडलों के स्थानीय प्रोडक्शन पर निर्भर थे। इसके अलावा कुछ स्वदेशी डिज़ाइन भी उपलब्ध थे। उस समय लोडिंग राइफल (एसएलआर) के बाद इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम (आईएनएसएएस) प्रचलन में आया, जिसके बाद स्टरलिंग सब–मशीनगन और 9 एमएम की ऑटो पिस्तौल चलन में आई। तब तक घरेलू उत्पादन पर ज़ोर कम होने लगा था, और ख़ास हथियारों के लिए आयात किए जाने लगे।

- 2008 से अबतक, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने घरेलू अधिप्राप्ति से आयातों के ज़रिए आधुनिकीकरण की शुरुआत की। इससे एकरूपता खत्म हुई क्योंकि सरकारी एजेंसियां और राज्य सरकारें अपनी–अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हथियारों की खरीद करने लगीं। सरकारी सेल्स पर से आईओएफ का एकाधिकार ख़त्म होने लगा, और फलस्वरूप अब उन्हें विदेशी सप्लायरों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है।

- इन तीन चरणों के ज़रिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर लिए। आगामी खंड में अधिप्राप्तियों और भारतीय सुरक्षा हथियारों की अनुमानित मात्रा का सर्वेक्षण किया गया है।

पहला चरण: ली–एन्फील्ड राइफल

अपने ज़माने के मशहूर और पुरातन बोल्ट–एक्शन ली–एन्फील्ड राइफल ने भारत में छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति की पहली आधुनिक लहर को परिभाषित किया। 1907 से 1974 के बीच आईओएफ ईशापुर ने इस राइफल के कई संस्करण निकाले। इसकी जगह दूसरे हथियार लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद 2013 के अंत तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अन्य हथियारों की बजाए इसी को इस्तेमाल में रखा हुआ है (देखें तालिका 1)।

ली–एन्फील्ड की सर्वविद्यमानता के बावजूद भारतीय ली–एन्फील्ड का इतिहास अभी तक समझा नहीं जा सका है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत ने तकरीबन 50,000 की दर से हर साल ली–एनफील्ड राइफलों को आयात करना शुरू किया (वॉल्टर, 2005, पृ. 87)। ब्रिटिश सरकार ने अपनी बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए स्थानीय प्रोडक्शन का फ़ैसला किया, और तमाम विरोधों के बावजूद हथियारों की घरेलू इंडस्ट्री शुरू कर दी गई। घरेलू प्रोडक्शन 1901 में शुरू हुआ (ओएफबी, 1999)। शुरू में लाइसेंसी उत्पादन में दिक्कतें आईं, लेकिन उसके बाद 1907 से सीरिज़ प्रोडक्शन शुरू हो गया, जिससे छोटे मैगज़ीन वाले ली–एन्फील्ड (एसएमएलई) एमके III को स्टैंडर्डाइज़ किया जा सका। अगले 60 सालों तक ये प्रोडक्शन में रहा (स्केर्नेटन, 1993,

तालिका 1: ईशापुर में राइफल प्रोडक्शन की दरों के दस्तावेज़ के तौर पर उदाहरण, 1939–2011

विवरण	प्रकार	कुल संख्या	साल	औसत सालाना दर	स्रोत
.303 ली–एन्फील्ड	बोल्ट–एक्शन	692,567	1938–45	115,000	स्केर्नेटन, 1993, पृ. 341
2ए1 ली–एन्फील्ड	बोल्ट–एक्शन	250,000	1963–74	22,000	स्केर्नेटन, 1993, पृ. 345
एसएलआर 7.65	सेमी–ऑटोमैटिक	350,000	1965–71	32,000	एगर, 2006
एसएलआर 7.65	सेमी– ऑटोमैटिक	300,000	1965–66	300,000	ग्राहम, 1984, पृ. 167–68
इनसास 5.56	ऑटोमैटिक	269,612	1998–2000	90,000	कैग, 2001, पैरा 47.1.11
इनसास 5.56	ऑटोमैटिक	100,000	2011	100,000	एमओडी, 2012

पृ. 331, 335)।

1926 में ब्रिटिश सरकार के पास 650,000 ली–एन्फील्ड राइफलें थीं। अगले साल सालाना प्रोडक्शन 60,000 के आस–पास हो गया, जिससे 1931 तक कुल सूची बढ़कर 830,000 राइफलों के आस–पास चली गई (स्केर्नेटन, 1993, पृ. 339–40)। इसके बाद प्रोडक्शन कम होता चला गया, और 1939–40 में सिर्फ 17,620 राइफलें बनीं या उनमें सुधार किया गया। लेकिन युद्ध के दौरान हथियारों की ज़रूरत महसूस हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कुल मिलाकर 692,567 राइफलें आईओएफ ने बनाईं (स्केर्नेटन, 1993, पृ. 341)। ये संख्या असरदार ज़रूर है, लेकिन इसे भारतीय सेना के अनुपात में देखा जाना चाहिए। अगस्त 1945 तक सेना में 25 लाख सैनिक थे, जिनके लिए ज़ाहिर तौर पर यूनाईटेड किंगडम से अतिरिक्त राइफलों का आयात किया गया (गाय,बॉयडन, एंड हार्डिंग, 1997, पृ. 172)।

1927 में कुछ ली–एन्फील्ड राइफलों को .410 मस्केट्स (शॉटगन) में पुलिस के इस्तेमाल के लिए तब्दील किया गया। दंगा नियंत्रण के लिए कम जानलेवा माने जाने वाले ये हथियार .410 ली–एन्फील्ड राइफलों से मॉडिफाइड रिसीवर, बैरल, फीड मेकैनिज्म और शॉटगन शेल्स के इस्तेमाल के लिहाज़ से अलग थे (स्केर्नेटन, 1993, पृ. 342)। ली–एन्फील्ड राइफ़ल पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा सबसे पुराना हथियार है, हालांकि जहां ज़रूरत पड़ी है, इसकी जगह दूसरे हथियार भी लाए गए हैं (राघवन, 1993; सिद्दिकी, 2009)। .410 मस्कट कन्वर्जन की संख्या ठीक–ठीक मालूम नहीं, लेकिन 2013 के अंत तक ये संख्या 250,000 के आस–पास अनुमानित थी (देखिए, 'पुलिस के कुल छोटे हथियार')

ली–एन्फील्ड्स आज़ादी के बाद भी 60 के दशक तक बनते रहे। 1962 के बाद ली–एन्फील्ड राइफल प्रोडक्शन ईशापुर 2ए1 के रूप में जारी रहा, जिसमें 7.62 X 51 मिमी की गोलियों का इस्तेमाल होने लगा। इन सेमी–ऑटोमैटिक राइफलों का इस्तेमाल भी उसी वक्त शुरू हुआ (स्केर्नेटन, 1993)। 250,000 ईशोपोर 2ए1 का प्रोडक्शन 70 के दशक के बीच में आकर बंद हुआ (1993, पृ. 345)। अन्य सूत्र बताते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तकरीबन 500,000 बंदूकें दी गई थीं (एमजीए, एन.डी.)। भारतीय हथियारों की अधिप्राप्ति की रूढ़ीवादिता को परिलक्षित करतीं ये ईशापुर 2ए1 बंदूकें मिलिट्री बोल्ट–एक्शन राइफल की वो आख़री नॉन–स्नाईपर किस्में हैं जो किसी सेना के लिए डिज़ाइन की गई (एमजीए, एन.डी.)।

आज़ादी के बाद ली–एन्फील्ड राइफलों के प्रोडक्शन और उनके मॉडल सालाना 22,000 से 115,000 की संख्या तक घटते–बढ़ते रहे। 65 सालों के ईशापुर के प्रोडक्शन का औसत 70,000 सालाना माना जा सकता है (स्केर्नेटन 1993, पृ. 341, 345)। इस दर से 1947 से लेकर 1970 के मध्य तक भारत में हथियारों का उत्पादन 20 लाख के आस–पास रहा होगा।

20 लाख के उत्पादन का ये अनुमान सरकारी नियंत्रण में मौजूद 21.5 लाख हथियारों के अनुमान के आस–पास है (19 लाख राइफलें और 250,000 शॉटगन)। हथियारों की कुल संख्या सप्लाई के दूसरे स्रोतों, ख़ासकर यूके से किए गए आयात और पहले के प्रोडक्शन पर भी निर्भर है। इस पर सिंगापुर में 1942 में किए गए समर्पण और 1947 में हुए बंटवारे का भी असर देखने को मिलता है। ये इनवेन्ट्री अफगानिस्तान में 80 के दशक में भेजी गई 100,000 बंदूकों के स्थानांतरण से भी प्रभावित हुई (यूसफ एंड एडकिन, पृ. 85)।

कई सारी ली–एन्फील्ड राइफलें सेना से भारतीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दी गईं, जहां उन्हें हटाकर दूसरे हथियार लाने की कोशिशों के बावजूद वे प्रचलन में बनी रहीं (कैग, 2010, पृ. 159)। आम लोगों के लिए उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है कि उनमें से कई हथियारों ने आम लोगों के हाथों में भी जगह बनाई (मारवाह, 2010, पृ. 23)। पिछले प्रोडक्शन, आयातों और निर्यात के बाद की संख्या को मिलाकर, देखा जाए तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास 2012 में 19 लाख के आस–पास ली–एन्फील्ड राइफलें थीं (देखिए तालिका 8)।

दूसरा चरण: छोटे हथियार

भारत में छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति के दूसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करने की कोशिश हुई, लेकिन तब भी घरेलू प्रोडक्शन और डिज़ाइनों पर नज़र बनी रही, जिससे नतीजे बेहद निराशाजनक निकले। अलग–अलग सप्लायरों के आने से हथियारों की किस्मों में विविधता आई, जिसमें एसएलआर और 9 एमएमऑटो पिस्टल शामिल थे। सीमित आयात की वजह से ये विविधता और बढ़ी। आयात किए जाने वाले हथियारों में हेकलर और कॉच एमपी5 सब मशीनगन भी शामिल थे जिन्हें 80 के दशक में भारत के वीआईरी प्रोटेक्शन फोर्स के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए विदेशों से मंगाया था (एज़ेल, 1988, पृ. 202)।

दूसरे चरण में घरेलू छोटे हथियारों की अतिरिक्त किस्में भी शामिल हुईं। इस विविधीकरण के साथ ही 1943 में कानपुर में, और 1967 में तिरुचिरापल्ली में नई फैक्ट्रियां भी खुलीं (ओएफबी, ए.डी.ए, ओएफबी, एन.डी.बी)। दूसरे चरण के अन्य उत्पादों में 5.56 मिमी के इनसास राइफल के हल्के मशीनगन और 7.62 मिमी के मीडियम मशीनगन शामिल थे (एमएमजी)। इन दो मशीनगनों को अभी भी सालाना 6,000 और 300 की संख्या में बनाया जा रहा है (एमओडी, 2012)। ब्रेन लाइन मशीनगनें और रूस की भारी मशीनगनों का भी कानपुर और तिरुचिरापल्ली में प्रोडक्शन शुरू हुआ।

सेल्फ–लोडिंग राइफल (एसएलआर)

1950 के दशक में ली–एन्फील्ड राइफलों का अप्रचलन और दूसरे छोटे हथियारों का चलन देखने को मिलने लगा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के.कृष्ण मेनन ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य एसएलआर के समारोह में। एसएलआर साठ के दशक से नब्बे के दशक तक भारतीय सेना का मुख्य हथियार रहा। अमृतसर, अक्टूबर 2010 © नरिंदर नानू/एएफपी/गेट्टी इमेजेज

की कोशिश की, लेकिन न आधुनिकीकरण हो सका, न हथियारों को बदला जा सका। 1962 में चीनी सेना के हाथों भारतीय सेना की हार के बाद ख़याल बदले। चीन की सेना के पास ज्यादा आधुनिक सेमी–ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक राइफलें थीं (कैविक, 1967, पृ. 91, 184)। हथियारों के इस पिछड़ेपन को महसूस करते हुए 1963 में पाकिस्तानी सेना ने जर्मनी में डिज़ाइन किए गए जी–3ऑटोमैटिक राइफलों को अपनी सेना में शामिल करने का फ़ैसला किया (ग्रॉलीन, 2001)।

भारत–चीन युद्ध ने भारतीय सेना के भारी विस्तार की ज़रूरत को बल दिया। सैनिकों की संख्या बढ़कर 830,000 हो गई (थॉमस, 1978, पृ. 184)। रक्षा सुधारों के पुरोधा नए रक्षामंत्री वाई.बी. चव्हाण ने सेना और ऑर्डनेंस कारखानों के विरोध के बावजूद छोटे हथियारों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया (प्रद्यान, 1998)। बेल्जियन एफएएल राईफल के एक सेमी–ऑटोमैटिक वर्ज़न को लाइसेंसिंग फीस से बचने के लिए पहले रिडिज़ाइनिंग के लिए चुना गया और एसएलआर यानी सेल्फ–लोडिंग राइफल के रूप में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ (स्मिथ, 1994, पृ. 81, एमओडी, 2012)। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेरलिंग सब–मशीनगन और 9 मिमी ऑटो पिस्टल का इसी पहल के दौरान प्रोडक्शन शुरू हुआ।

घरेलू डिज़ाइनों और सेना–औद्योगिक स्व. निर्भरता की वकालत करने वालों के अलावा एफएएल राइफल एक गैर–विवादित चुनाव था (प्रधान, 1998)। बेल्जियन–डिज़ाइन वाली एफएएल अपने ज़माने की वो पाश्चात्य बंदूकें थीं जिन्हें सेना हासिल कर चुकी थी, और भारतीय सेना इससे प्रभावित थी (लॉन्ग, 1998, पृ. 19–21)। ली–एन्फील्ड जैसी नाटो गोलियों वाली इन बंदूकों की रेंज और क्षमता पुराने राइफलों से बेहतर थी। सेमी–ऑटोमैटिक एक्शन ने, जिसमें गोलियों की खपत के लिए हर शॉट के लिए एक अलग ट्रिगर को दबाने की ज़रूरत पड़ती है, एफएएल राइफलों को एक ज़ाहिर पसंद बना दिया। इसका भारतीय वर्ज़न, एफएएल राइफल ही, मेट्रिक नाप और avoirdupoi का मिला–जुला इस्तेमाल करता है (स्केर्नेटन, 1993, पृ. 345)। इन्हें ईशापुर राइफल कहा जाता है, और उन्हें ली–एन्फील्ड से अलग मानना चाहिए, हालांकि दोनों को कई बार एक ही नाम दे दिया जाता है।

कुल एसएलआर प्रोडक्शन को अभी तक आम नहीं किया गया है। एक रिर्पोट के मुताबिक 1965 से 1971 के बीच 350,000 यूनिटें बनीं (देखिए तालिका 1, एगर, 2006)। ये संख्या ज्यादा नहीं है। एक और लेखक ने लिखा है, '1965 युद्ध के तुरंत बाद ऑर्डनेंस कारखाने दस घंटों की दो शिफ्टों में चला करती थीं, और 25,000 ईशापुर राइफलें एक महीने में बना करती थीं...' यानी अगले ही साल 300,000 राइफलें बनी होंगी (ग्राहम, 1984, पृ. 167–68)। हालांकि इन्हें इनसास राइफलों से रिप्लेस किया जाना था, लेकिन एसएलआर 50 सालों बाद भी प्रोडक्शन में रही और भारतीय पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाती रही हैं (कैग, 2010, पृ. 4–5; एमओडी, 2012; गंगन, 2011)।

9 मिमी ऑटो पिस्टल

भारत में सेना और पुलिस अफसरों को साइडआर्म्स यानी हैंडगन्स दिए गए। पहला आधुनिक साइडआर्म जो भारत में बड़ी मात्रा में बनाया गया, वो था वेब्ले एमके IV रिवॉल्वर, जो 1900 की शुरुआत में फिरोज़पुर में बनाया गया, जिसके बाद प्रोडक्शन ईशापुर और कानपुर चला गया (रॉय, 2003; पृ. 409)। आम नागरिकों के लिए वेब्ले के रिवॉल्वर अभी भी बनाए जा रहे हैं (एमओडी, 2012)। 1963–64 में सेना के लिए रिप्लेसमेंट मांगा गया, जो शायद उसी रक्षा कार्यक्रम के तहत था जिसके दौरान एसएलआर बंदूकें दी गईं।

9 मिमी वाली पिस्टल अभी भी सेना और पुलिस का स्टैंडर्ड साइडआर्म है। बेल्जियन–मेड बाउनिंग एफएन हाई पावर, दुनिया की सबसे मशहूर पिस्तौलों में से एक, की नकल जब भारत में आई जो काफी पसंद की गई (वैलपॉलिनी, 2009)। इसका उत्पादन 1963 से शुरू हुआ और 2012 तक भी प्रोडक्शन रेट में बहुत परिवर्तन नहीं आया और सालाना औसत 12,000 बंदूकें बनती रहीं (देखिए, 'भारतीय ऑर्डनेंस कारखानों का भविष्य'। इसकी तकरीबन 650,000 बंदूकें बनीं, जो अभी भी शायद सर्विस में हैं।

हालांकि ये पहली बड़ी–क्षमता वाली मैग़ज़ीन पिस्तौलें थीं (13 गोलियों वाली) और सर्विस लायक बनी रहती हैं, लेकिन फिर 9 मिमी ऑटो पर उम्र जल्दी हावी हो जाती है। इसमें सुरक्षा फीचर्स भी कम हैं, और आधुनिक डिज़ाइनों के मुक़ाबले क्षमता भी कम है। अनाधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि भारत में चेक सीज़ी 75 पिस्तौलें भी बन रही हों, जो ब्राउनिंग एम1911 की कम–कीमत वाला वर्ज़न है, और इसमें भी 9 मिमी गोलियों का इस्तेमाल होता है (रॉबर्ट्स, 2011)।

स्टर्लिंग सब–मशीनगन

सब–मशीनगनें आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं, और आमतौर पर वीआईपी सुरक्षा जैसे ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल में आती हैं। भारत में सब–मशीनगनों को अक्सर कार्बाइन कहा जाता है, और ये पसंद किए जाने वाले हथियारों में से एक मानी जाती हैं। ब्रिटिश डिज़ाइन वाली स्टर्लिंग सब–मशीनगनों को 60 के दशक में आयात किया गया था, और कुल 32,536 बंदूकें खरीदी गई थीं (थॉमसन, 2012)। घरेलू उत्पादन उसी दौरान आईओएफ कानपुर प्लांट (आईओबी, एन.डी.) में शुरू हो गया था। हालांकि उत्पादन पहले शायद ज्यादा था, 2012 में इसका औसत सालाना उत्पादन 5,000 के आस–पास था

तालिका 2: भारत सरकार द्वारा किए गए हथियारों के चुनिंदा आयात; 1995–2012

खरीदार	सप्लायर	विवरण	किस्म	संख्या	डिलीवरी	स्रोत
सेना	रोमानिया	कलाशनिकोव–पैटर्न	ऑटोमैटिक राइफल	100,000	1995	फोरकास्ट, 2012
स्पेशल फोर्सेस	इज़रायल	तावोर	ऑटोमैटिक कार्बाइन	3,070	2007	डीआईडी, 2007
गृह मंत्रालय	स्विट्ज़रलैंड	एसजी551	ऑटोमैटिक राइफल	675	2010	ऑल इंडिया, 2012
गृह मंत्रालय	रशियन फेडरेशन	कलाशनिकोव–पैटर्न	ऑटोमैटिक राइफल	29,260	2010–12	ऑल इंडिया, 2012
गृह मंत्रालय	इज़रायल	X95 9 MM	सब–मशीन गन	12,000	2012	उन्निथन, 2011
गृह मंत्रालय	इटली	Mx4 9 MM	सब–मशीन गन	34,000	2011–12	बैडले, 2012, पृ.28

(देखिए तालिका 3)। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर 400,000 यूनिटें खरीदी गईं।

इसमें फिलहाल 380,000 से 400,000 की संख्या में सब–मशीनगनों के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी है: 160,080 सेना के लिए, और बाकी अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए (बेदी, 2012ए)। एक और ज़रूरी अध्ययन के मुताबिक 90 के दशक तक कुल आईओएफ प्रोडक्शन 10 लाख स्टर्लिंग्स था (लायडलर एंड हाउरायड, 1995, पृ. 211)।

इनसास राइफल

1970 के दशक में सेना में अंतर्राष्ट्रीय चलन एसएलआर जैसे राइफलों से हट रहा था। इसकी जगह छोटी गोलियों वाले पूरी तरह ऑटोमैटिक राइफलों ने ले ली, जिनमें नाटो–स्टैंडर्ड 5.56 ग 45 मिमी वाली गोलियों का इस्तेमाल होता था। 1980 में ली–एन्फील्ड्स बड़ी संख्या में अभी भी रिप्लेस हुए नहीं थे, भारतीय सेना एसएलआर को रिप्लेस करने के लिए तैयार थी (गुरुस्वामी, 2006)।

नवंबर 1982 में शुरुआती डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट पुणे के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट को दिया गया (कैग, 1995, पैरा. 40.1)। विकास धीमी गति से हो रहा था। 1983 से 1987 के बीच ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) ने टेस्टिंग के लिए सिर्फ 36 नई राइफलें निकालीं (कैग, 1995, पैरा 40.5. 1)। जहां बाकी के हथियारों के बारे में सोचा जा रहा था, '1987 में सेना की ईशापुर के जगह कोई और राइफल चुनने में किए गए धोखे की वजह से कड़ी आलोचना हुई' (स्मिथ, 1994, पृ. 117)।

नई राइफलों को 1988 तक सर्विस में आना था, भारतीय सेना को 1998 तक पूरी तरह नए हथियारों से लैस होना था, लेकिन ये ध्येय हासिल करना नामुमकिन था (कैग, 2001)। ये शायद संयोग नहीं है कि 80 के दशक में 10 मिलियन ईस्ट जर्मन एके–74 राइफलें ऑर्डर करने के लिए जांच बिठाई गई थी, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं निकला (एज़ेल, 2001, पृ.140–41)। ये बताना मुश्किल है कि समझौता पूर्वी जर्मनी के पतन से हुआ, या इसलिए क्योंकि आईओएफ पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया था।

उसकी जगह इनसास राइफल को सेना की स्टैंडर्ड राइफलें बना दिया गया (कैग, 2001, पैरा 47)। 5.56 मिमी डिज़ाइन वाली ये राइफलें ख़ास हैं, लेकिन कलाशनिकोव जैसी विदेशी राइफलों से प्रेरित हैं, और इनमें एसएलआर और बाकी राइफलों के फीचर्स भी हैं (कटशॉ2006, पृ. 370–71)। इनसास परिवार में 5.56 मिमी कार्बाइन और लाइट मशीनगन (एलएमजी) भी शामिल है।

ये नई राइफलें राइफल फैक्ट्री ईशापुर में बनने वाली थीं और बाद में आईओएफ के तिरुचिरापल्ली प्लांट में, जबकि एलएमजी और कार्बाइन वर्ज़न कानपुर में बननी थीं (कैग, 2001, पैरा 47.3)। अगस्त 1993 में सेना ने 210,000 राइफलों का ऑर्डर दिया, जिन्हें 1998 तक डिलीवर करना था। राइफलों की कुल ज़रूरत 528,000 थी। लेकिन पूरी तरह प्रोडक्शन 1998 में शुरू नहीं हुआ। कुल मिला 269,612 राइफलें 2000 की शुरुआत तक बनीं, यानी सालाना तकरीबन 80,000 (कैग, 1995, पैरा 40.8.1; कैग, 2001, पैरा 47.7.1. 1)।

इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी इनसास राइफलों की सर्विस में आने से पहले ही खूब आलोचना हुई। 1997 में ये आलोचनाएं संसद तक पहुंच गईं, जिस समय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सारे हथियार सर्टिफाइड थे और ख़राब हथियारों के आरोपों को सिरे से नकार दिया (राज्य सभा, 1997)। साल 2000 संसद में उठाए गए एक सवाल पर रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि सेना ने इनसास राइफलें स्वीकार की थीं और इनका प्रदर्शन 'संतोषजनक' रहा (राज्यसभा 2000ए)।

इनसास राइफलों के बनने के स्टैंडर्ड को लेकर आलोचनाएं सिर्फ भारत में ही सामने नहीं आई। इनसास की सबसे बड़ी आयातक नेपाली सेना भी ख़ासतौर पर असंतुष्ट थी (कार्प, 2013बी)। शुरू में शिकायतें डेवलपमेंट की शुरुआती परेशानियों को लेकर रही होंगी, लेकिन डेवलपमेंट के दो दशक बाद भी ये संतोषजनक नहीं रहीं। ऐसा माना जाता है कि कार्बाइन वर्ज़न कभी सीरिज़ प्रोडक्शन के लिए बना ही नहीं। ऐसा लगता है कि इसे वैकल्पिक डिज़ाइनों के लिए छोड़ दिया गया, और प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 25 साल बाद भी इनके डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है (राघवन एंड आनंद, 2009)।

इनसास राइफलों की कुल संख्याओं के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2000 तक 300,000 राइफलें बन चुकी थीं और अगले साल 80,000 और बननी थीं (राज्य सभा, 2000ए)। इस दर से 528,000 की शुरुआती ज़रूरत 2002–03 तक पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट दी कि औसतन 100,000 यूनिटें सालाना बनती रहीं (एमओडी, 2012)। इसका मतलब है कि तकरीबन 14 लाख के कुल ऑर्डर में से 900,000 राइफलें बन चुकी थीं। ये अनुमान ऊँचा लगता है, क्योंकि अभी भी कई सेना यूनिटों को आधुनिक राइफलें मिलनी बाकी हैं (बेदी, 2012बी)। ज्यादा सही अनुमान 2012 तक 700,000 से 900,000 राइफलों के बनने का है।

तीसरा चरण: 2008 से अभी तक

घरेलू इंडस्ट्री में जैसे–जैसे निराशा बढ़ती गई, रक्षा और गृह मंत्रालयों के द्वारा भी स्वर्निभर और सक्षम सैन्य उद्योग को सहयोग कम होता गया। इनकी जगह हथियारों की अधिप्राप्ति में भारी–भरकम, प्रचलित हथियारों को जगह मिलने लगी। सेना और पुलिस के हथियारों में लंबे समय से नज़र आ रही एकरूपता घटने लगी।

छोटे हथियारों का तीसरा चरण भारत के स्पेशल फोर्सेस ने शुरू किया, जिसने 80 के दशक में अलग–अलग किस्म के असलहों को जमा करना शुरू किया (शर्मा, 2008, पृ. 73, 109, 131, 151, 258)। अधिप्राप्ति में विविधता

के पीछे 1993 से 1995 के बीच कलाशनिकोव पैटर्न की राइफलों को हासिल करने का फ़ैसला था। ये फ़ैसला अपवाद था, हालांकि 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों ने छोटे हथियारों के आयात के आधिकारिक विरोध को खत्म कर दिया और छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति की एक तीसरी लहर शुरू हुई।

कलाशनिकोव–पैटर्न राइफल

भारतीय सेना सोवियत में बने इस हथियार पर 60 के दशक से निर्भर होने लगी और इस हथियार के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गई (स्मिथ, 1994, पृ. 82–84, 94–98)। लेकिन भारत ने भूतपूर्व सोवियत यूनियन के इस हथियार, कलाशनिकोव को पूरी तरह नहीं अपनाया। इसे शायद भारत की सेना पर ब्रिटिश प्रभाव माना जा सकता है, जो नाटो–क्षमता वाले असलहों पर यकीन करती थी, और पूरी तरह ऑटोमैटिक इस हथियार को संदेह से देखती थी। ऑटोमैटिक राइफल वाले दुश्मनों से 1987 में श्रीलंका में भिड़ंत हुई। पूर्वी जर्मनी से 1987–88 में कलाशनिकोव न खरीदने पर 90 के दशक में दबाव बढ़ने लगा, जब कश्मीर में, या फिर नक्सली समूहों से या पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादियों से गुरिल्ला तरीके से भिड़ंत होने लगी (कार्था, 1993)। एज़ेल की रिर्पोट के मुताबिक करीब 20,000 कलाशनिकोव कश्मीर, पंजाब और बाकी जगहों से ज़ब्त किए गए और फिर उन्हें आधिकारिक इस्तेमाल में डाल दिया गया, जो शायद इस प्रकार का पहला आधिकारिक इस्तेमाल था (एज़ेल, 2001, पृ. 186)।

पकड़े गए हथियारों के अलावा भारतीय अर्धसैनिक बल अपने ली–एन्फील्ड राइफलों से अलगाववादियों के हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। इनसास राइफलों में देरी हुई तो सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स के लिए 1993 में 100,000 कलाशनिकोव पैटर्न की राइफलें खरीदीं। शुरू में सेना ने एक बुल्गेरियन सप्लायर से बात की और असलहों के लिए उत्तरी कोरिया से संपर्क किया। लेकिन कुछ मुश्किल वजहों से गृह मंत्रालय ने रोमानिया के साथ जून 1995 में राइफलों के लिए और दिसंबर 1996 में असलहों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया (कैग, 2001, पैरा 47.8; राज्यसभा, 2000बी)। कलाशनिकोव क्यों चुना गया, ये बात आम नहीं की गई। 88 अमेरिकी डॉलर की कीमत वाला बेहद सस्ता राइफल इसकी वजह रहा होता (फोरकास्ट, 2012, पृ. 5–6)। 2013 में भी राष्ट्रीय राइफल्स यही हथियार इस्तेमाल कर रहा था (इंडिया टुडे, 2013)।

कलाशनिकोव–पैटर्न के राइफल विविधता की ओर एक कदम थे। लेकिन सोवियत–स्टाइल के छोटे हथियारों की तरह कोई और खरीद नहीं हुई। 2002–03 में 64,000 कलाशनिकोव खरीदने की कोशिश ज़रूर असफल रही, जब बुल्गेरिया की एक कंपनी के साथ सौदेबाज़ी समझौते पर लाइसेंसी नियंत्रण रखने की रूस की मांग सामने आई (खन्ना, 2004)। शुरू में हुआ कलाशनिकोव समझौता भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़े पैमाने पर अधिप्राप्ति की वजह नहीं बना, लेकिन भारत की घरेलू हथियारों पर निर्भरता को कम ज़रूर कर दिया और बड़े पैमाने पर आयात की ये पहली घटना देखी गई (ऑल इंडिया, 2012)।

आयात में बढ़ोतरी

70 और 80 के दशक में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई किस्म के विदेशी हथियार ऑर्डर किए, लेकिन उनकी संख्या कम ही रही (एज़ेल, 1988, पृ. 201–201)। कलाशनिकोव के राइफल समझौते के साथ हुई शुरुआत बड़े विदेशी समझौतों में तब्दील हो गई, जो 90 के दशक और उसके बाद आम होने लगा। जिस ऑर्डर को ख़ासी पब्लिसिटी मिली, वो था 2002 में विशेष सुरक्षा बल के लिए लिया गया इज़रायल में बने 3,074 तावोर टीएआर–21 कार्बाइन (राज्यसभा 2005)। ये कार्बाइन 2007 में 88 करोड़ रुपए (20 मिलियन यूएस डॉलर) में खरीदे गए थे (डीआईडी, 2007)।

2008 के मुंबई हमलों के बाद हथियारों के आयात में अचानक तेज़ी आई। देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली मुंबई पुलिस अब तक आतंकवादियों के कलाशनिकोवों और ग्रेनेडों के आगे पुराने ली–एन्फील्ड राइफलों का इस्तेमाल करती आ रही थी। सीनियर पुलिस, जिनमें बॉम्बे पुलिस आतंकवाद–विरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख हेमंत करकरे शामिल थे, इसलिए मारे गए क्योंकि उनका सुरक्षा कवच कलाशनिकोव के हमलों के आगे अप्रभावी साबित हुआ।

घरेलू उत्पादक अचानक तेज़ी से बढ़ी इस मांग को पूरा करने में अक्षम थे, इसलिए विदेशी हथियार बड़ी मात्रा में खरीदे जाने लगे। इन सभी आयात में केन्द्र सरकार द्वारा की गई खरीद को सबसे अच्छी तरह दस्तावेज़ों में समेटा गया है (देखिए तालिका 2)। विभिन्न राज्यों और शहरों की पुलिस को भी नए हथियार दिए गए, लेकिन उनका रिकॉर्ड अक्सर नहीं मिलता है। जहां इन हथियारों की किस्मों का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, उनकी संख्या और अधिप्राप्ति की तारीख़ें नहीं पता लगाई जा सकतीं (एनसीआरबी, 2012, पृ. 167)। मुमकिन है कि भारतीय नगरपालिका और राज्य के पुलिस बल ने लाखों की संख्या में हथियार खरीदे हों।

हाल में खरीदे गए हथियारों में कई प्रकार की किस्में मिलती हैं। इनमें से सबसे आम ग्लॉक पिस्तौलें हैं, जो फायर करने की क्षमता, सादगी और सुरक्षा की वजह से काफी पसंद की जाती रही हैं। मुंबई पुलिस जैसे कुछ अपवाद भी हैं, जिसने अपने कॉन्स्टेबलों और अफ़सरों को स्मिथ एंड वेसन पिस्तौलें दीं

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स जर्मनी से आयातित हेकलर एंड कोच एमपी5 सब–मशीनगनों के साथ, जिनका इस्तेमाल वीआईपी सुरक्षा के लिए होता है। मुंबई, जून 2009 © इंद्रनील मुखर्जी/एएफपी/गेट्टी इमेजेज

(स्वामी, 2009)। उत्तर प्रदेश ने अपनी पुलिस फोर्स को जर्मन एमपी5 सब–मशीनगनें दीं (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2012)।

आयात में होने वाली इस बढ़ोतरी की वजह से केन्द्र सरकार की बलों के शस्त्रीकरण पर भी फर्क पड़ा। आज़ादी के बाद जिस एकरूपता ने शुरू के 50 सालों के शस्त्रीकरण को प्रभावित किया था, अचानक बेमानी हो गया क्योंकि सभी एजेंसियां हथियारों के आधुनिकीकरण में लग गईं। आईओएफ की भूमिका भी प्रभावित होने लगी थी, और अब घरेलू ज़रूरतों पर उनका एकाधिकार नहीं रह गया था। पहले आईओएफ जहां छोटे हथियारों के डिज़ाइनों को शिकायतों के बावजूद खरीदारों को देता आ रहा था, वहां अब समझौतों और खरीद के लिए प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ता था, और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही।

आयात के साथ विकेन्द्रीकरण ने कुछ ख़ास सुरक्षा एजेंसियों को प्रॉडक्ट की एक बड़ी रेंज दी। मसलन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (विशिष्ट आतंकवाद–विरोधी दस्ता) पहले जर्मन एमपी 5 सब–मशीनगनें इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में नई स्विस एसआईजी एसजी 551 ऑटोमैटिक राइफलें इस्तेमाल करने लगा (ऑल इंडिया, 2010)।

भारतीय ऑर्डनेंस कारखानों का भविष्य

आयात से जहां आधुनिक हथियार मिलते हैं, वहीं आईओएफ अभी भी भारत में आधिकारिक उत्कृष्ट हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आईओएफ अपने खरीदारों के लिए सालाना 130,000 हथियार बनाता है, और इनके अलावा अतिरिक्त 47,600 हैंडगन, राइफलें और शॉटगन आम जनता की खरीद के लिए बनाई जाती हैं (देखिए तालिका 3)।

आईओएफ छोटे हथियार बनाता है जो पुराने हो चुके हैं। बल्कि कई डिज़ाइन तो 1950 या उससे भी पहले के हैं, जिनमें इकलौता अहम अपवाद इनसास परिवार के हथियार हैं जो 65 साल पुराने कलाशनिकोव डिज़ाइन पर आधारित हैं। इनसास राइफलें अभी भी ईशापुर, कानपुर और तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही हैं (एमओडी, 2012)। आकंड़े बताते हैं कि एसएलआर, जिन्हें रिप्लेस करने के लिए इनसास राइफलें बनाई गई थीं, अभी भी प्रोडक्शन में है। स्टर्लिंग सब–मशीनगन और 9 मिमी ऑटो पिस्टल भी अभी प्रोडक्शन में हैं, हालांकि इन्हें और आधुनिक आयात से रिप्लेस किया जाने लगा है।

सेल्स के लिए स्पर्धा में दौड़ रही आईओएएफ ने हाल ही में मौलिकता भी दिखाई है। फिलहाल मौजूद प्रॉडक्ट्स की नई किस्मों के अलावा, ज़िटारा कार्बाइन और ऐसी ही कई ऑटोमैटिक राइफलों की रेंज लॉन्च की गई है। हालांकि, इन नए प्रॉडक्ट में से विध्वसंक एंटी–मैटिरियल राइफलें ही सर्विस में हैं।

गोलियों का उत्पादन

भारत में छोटे हथियारों की गोलियों की प्रोडक्शन के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईओएफ ने तकरीबन एक अरब गोलियां बनाईं (स्केर्नेटन, 1993, पृ. 340)। 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद अमेरिका ने सैन्य सहायता के तौर पर 1963 में दो अतिरिक्त असेम्बली लाइनें भारत भेजीं, जो हर रोज़ लाखों की संख्या में गोलियां बना सकती थीं। 2009 तक आईओएफ ने सालाना 1710 करोड़ गोलियां बनाई थीं (राज्यसभा, 2009)।

ये संख्या ज़रूर बड़ी दिखती है, लेकिन 4.5 मिलियन सुरक्षाकर्मियों की तुलना में ये संख्या सालाना प्रति सुरक्षाकर्मी मात्र 38 गोलियां हैं। इसकी तुलना में 11 सितंबर 2011 के पहले अमेरिका में पीसटाइम ट्रेनिंग के दौरान 4400 करोड़ गोलियां सालाना बन रही थीं, और हर सैनिक को सालाना 366 गोलियां औसतन दी जा रही थीं (मेंगेल एंड ब्रॉन, 2005, पृ. 10; आईआईएसएस 2000, पृ. 25)। संघर्ष के दौरान और गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने सालाना 180 करोड़ गोलियों का इस्तेमाल किया (बनकॉम्ब, 2011)। जब तक गोलियों के स्टॉक को बड़े आयातों से पूरा न किया जाए तब तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ट्रेनिंग और ऑपरेशन्स के दौरान गोलियों की कमी महसूस करती रहेंगी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आयातित हथियारों के लिए आयात की हुई गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि 1995 के दौरान कलाशनिकोव राइफलों की खरीद के दौरान हुआ था (कैग, 2001, पैरा 47.8)।

राज्यों में छोटे हथियारों की कुल संख्या

तालिका 3. वार्षिक आईओएफ हथियार प्रोडक्शन, 2012

किस्म	विवरण	पहला प्रोडक्शन	वार्षिक प्रोडक्शन
आधिकारिक प्रयोग			
5.56 मिमी इनसास ऑटोमैटिक राइफल	ऑटोमैटिक राइफल	1994	100,000
5.56 मिमी इनसास एलएमजी	लाइट मशीन गन	1997?	6,000
7.62 मिमी एसएलआर	एफएएल सेमी–ऑटोमैटिक राइफल	1963	6,000
7.62 मिमी एमएमजी	मीडियम मशीनगन, एफएन–एमएजी	–	300
9 मिमी ऑटो	एफएन35 पिस्टल	–	12,000
9 मिमी कार्बाइन	स्टर्लिंग सब–मशीन गन	1967	5,000
आधिकारिक प्रयोग कुल			129,300
सिविलियन प्रयोग			
.315 स्पोर्टिंग राइफल	सिविलियन, ली–एन्फील्ड आधारित	1956	14,000
.22 स्पोर्टिंग राइफल	सिविलियन आरएफ	1971	600
.22 रिवॉल्वर	सिविलियन .22 एलआर	2002	2,500
.32 रिवॉल्वर	सिविलियन वेबले आईसीएफ	1980	22,000
.32 पिस्टल	सिविलियन ब्राउनिंग 1910	–	8,500
12 बोर सिंगल–बैरल	सिविलियन शॉटगन	1953	–
12 बोर डबल–बैरल	सिविलियन शॉटगन	1953	–
सिविलियन प्रयोग कुल			47,600
आईओएफ द्वारा कुल वार्षिक स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन, 2012			170,900

नोट्सः ये तालिका संपूर्ण नहीं है। इस गणना में विध्वंसक, ग्रेनेड लॉन्चर्स और स्नाईपर राइफल्स जैसे कुछ खास हथियार शामिल नहीं हैं जो प्रोडक्शन में हैं। इस गिनती में सारे सिविलियन शॉटगन्स भी शामिल हैं।

स्रोतः एमओडी (2012)। ओएफबी (2005) में स्टर्लिंग सब–मशीनगन का प्रोडक्शन शुरू। ओएफबी (1999) में सिविलियन हथियार प्रोडक्शन खरीदे जाने का पहला साल, .22 राइफल दक .32 रिवॉल्वर के प्रोडक्शन के अलावा (स्केनेर्टन से,1993, पृ. 345)

भारत में आधिकारिक तौर पर खरीदे गए छोटे हथियारों की संख्या आमतौर पर दर्ज की जाती हैं, लेकिन छोटे हथियारों के कुल शस्त्रागरों के आकार का ठीक–ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जब तक एकदम सटीक आंकड़े उपलब्ध न हों, सीमित आंकड़ों के आधार पर ही कुल संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।

ये भी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से पुराने हथियारों के अलग कर दिए जाने का कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस इश्यू ब्रिफ की रिसर्च के दौरान अतिरिक्त हथियारों की डीकमिशनिंग या विनष्ट किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस अनुमान में युद्ध के दौरान हथियारों को हुए नुकसान और टूट–फूट गए हथियारों की संख्या को बस अनुमानित मान लिया जाता है। इसके अलावा कमियों को पुराने सैन्य या पुलिस हथियारों की निजी मिल्कियत के आधार पर गिना जाता है या फिर उन निर्यातों के आधार पर, जैसे अफगानिस्तान भेजी गई ली–एन्फील्ड राइफलें या बार–बार मिले ये सबूत कि आतंकवादी आमतौर पर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते पाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी करती हैं।

सेना में छोटे हथियारों की कुल संख्या

सेना की कुल इन्वेंट्री के बारे में *Futuristic Infantry Soldier as a System* (एफ–इनसास) नाम के एक कार्यक्रम से पता चलता है, जिसमें भारतीय सेना की इन्फेंट्री में 2 करोड़ नई ऑटोमैटिक राइफलें जोड़ी गई (बेदी, 2012बी, पृ. 40)। 305,000 इन्फेंट्री को दिए जाने वाले नए उपकरण भी शामिल हैं जिनके पास आधुनिक हथियार नहीं हैं (बेदी, 2012बी, पृ. 44)। इनमें और किस्मों को भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें हैंडगन और मशीनगन शामिल हैं। सेना की दो करोड़ ऑटोमैटिक राइफलों की ज़रूरत हर किस्म के छोटे हथियारों की 2.5 करोड़ की ज़रूरत से मिलती जुलती है, जिसमें हैंडगन, मशीनगन और बाकी किस्म की बंदूकें शामिल हैं (स्मॉल आर्म्स सर्वे, 2006, पृ. 56)। रिज़र्व यूनिटों के लिए, ख़ासतौर पर जिनके पास पुराने हथियारों के होने का अनुमान लगाया जाता है, इस शोध में माना जा रहा है कि उनके सक्रिय साथियों की तुलना में मौजूद हथियारों की संख्या आधी है (देखिए तालिका 4)।

तालिका 4 में दिखाया गया है कि कैसे सेना का भारत के कुल छोटे हथियारों पर वर्चस्व है। थल सेना और सेना रिर्ज़व कंट्रोल के पास कुल 95 फ़ीसदी सैन्य छोटे हथियार हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि थलसेना में सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है। तीनों सेनाओं में से 84 प्रतिशत सैनिक थल सेना की यूनिफॉर्म पहनते हैं। थल सेना और कोस्ट गार्ड को छोड़कर सभी सैन्य सेवाएं ज्यादातर अपनी गार्ड ड्यूटिज़ के लिए हथियारों का इस्तेमाल करती हैं।

तालिका 4. भारतीय सेना की छोटी हथियारों की जरूरत का आकलन, 2012

संस्था	कर्मचारी	प्रति व्यक्ति अनुमानित हथियार	कुल हथियार
थलसेना	1,129,900	1.8	2,000,000
जलसेना	58,350	0.25	14,500
वायुसेना	127,200	0.25	32,000
कोस्ट गार्ड	9,550	1.8	17,000
थलसेना रिजर्व	960,000	0.5	480,000
जलसेना रिजर्व	55,000	0.125	7,000
वायुसेना रिजर्व	140,000	0.125	17,500
कुल	2,480,000		2,600,000

नोटः राउंडिंग की वजह से कुल संख्या में अंतर संभव।

स्रोतः आईआईएसस से कर्मचारी आंकड़े (2012, पृ. 243); कार्प से लिए गए अनुपात (2013ए).

पुलिस में छोटे हथियारों की कुल संख्या

भारत में आधिकारिक तौर पर मौजूद छोटे हथियारों की संख्या का बड़ा हिस्सा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पास है। पारंपरिक तौर पर भारतीय पुलिस कॉन्स्टेबल बिना हथियारों की पेट्रोलिंग करते हैं। आमतौर पर दंगों के दौरान भी पुलिस लाठी या बांस के कवचों पर निर्भर रहती है। लेकिन हथियार उनके पास होते हैं। आज़ादी के बाद से पुलिस के पास आमतौर पर सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ली–एन्फील्ड राइफलें रहीं, जिन्हें बाद में .410 मस्कट (शॉटगनों) में बदल दिया गया, क्योंकि इन्हें दंगा नियंत्रण के लिए कम घातक माना जाता है। सब–इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के अफसरों को आमतौर पर वेब्ले रिवॉल्वर दिया जाता था, और हाल में 9 मिमी ऑटो पिस्तौलें दी जाने लगीं। ये पारंपरिक रूप से इस्तेमाल में आनेवाली बंदूकें थीं।

इस पारंपरिक एकरूपता में 90 के दशक में हुए आधुनिकीकरण के बाद कमी है। पुलिस शस्त्रागरों में बड़ी संख्या में बंदूकों की कई प्रकार की किस्में अलग–अलग प्रोड्युसरों से लाई गईं। ग्लॉक हैंडगन, जिसे कम अनुभव रखने वाले सुरक्षाकर्मियों के लिए आदर्श माना जाता था, राज्य पुलिस की इन्वेंट्री में शामिल होने वाली बंदूकों में से एक थी (स्वामी, 2009)।

इस बदलाव की एक और वजह 2000–01 में आई, जब गृह मंत्रालय ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Forces) के कार्यक्रम को विस्तार दिया और इनसास जैसे नए हथियारों की खरीद में सब्सिडी देने लगे (अर्न्स्ट एंड यंग, 2010, पृ. 84)।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में जो एक कमी दिखाई दी, वो राज्यों को दिए गए बजट को खर्च कर पाने की अक्षमता थी, जिससे गहरी ब्यूरोक्रैटिक समस्याओं का पता चलता है (सिन्हा, 2012)। एमपीएफ की बाकी समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनमें बेहतर हथियारों की वजह से पुलिसकर्मियों के बढ़े हुए मनोबल पर ज़ोर दिया गया है (बीपी. आरडी, 2010)। एमपीएफ का एक और कम विवादित नतीजा पुलिस शस्त्रों के विविधीकरण को लेकर है, जिसमें कलाशनिकोव, एमपी5 सब–मशीनगनें, 9 मिमी कार्बाइन, ग्लॉक पिस्तौलें और ग्रेनेड लॉन्चर्स शामिल हैं। इनके अलावा इनमें घरेलू हथियार जैसे एसएलआर और इनसास राइफलें भी शामिल हैं (राज्यसभा, 2010)। सैन्य सर्विस में छोटे हथियार भारतीय पुलिस में भी आम होने लगे हैं।

भारतीय पुलिस के हथियारों की हालत भारत के कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में सामने आई थी (इंडियन एक्सप्रेस, 2009)। इसमें दिखाया गया है कि गुजरात में 2009 में 71,670 कॉन्सटेबलों और ऑफिसरों के लिए 74,577 राइफलें थीं (देखिए तालिका 5), यानी प्रति व्यक्ति 1.05 हथियार। ऐसे ही अनुपात बाकी जगहों पर पाए गए। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में छत्तीसगढ़ में 49,143

हथियार थे, जिनमें पुरानी पड़ चुकी बंदूकें भी थीं, जो अभी इस्तेमाल हो रही थीं (मुंबई मिरर, 2012)। 2011 में 44,107 पुलिसकर्मियों में प्रति व्यक्ति 1.1 से थोड़े ज्यादा हथियारों का औसत बताया गया (एनसीआरबी, 2012, पृ. 587)।

देश में अभी कुल कितने हथियार हैं, ये निश्चित तौर पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ राज्यों के उदाहरण लिए जा सकते हैं। 31 दिसंबर 2011 को भारत में कुल 1,660,151 पुलिसकर्मी थे जिनमें सिविल और सशस्त्र, दोनों शामिल हैं (एनसीआरबी, 2012, पृ. 167)। गुजरात के 1.05 बंदूक प्रति पुलिसकर्मी की दर से पुलिस की इनवेंट्री में तकरीबन 17 लाख हथियार हैं। इसे तरीके से गणना की जाए तो पुलिस द्वारा इस्तेमाल में आ रहे छोटे हथियारों की संख्या का भी अनुमान लगाया जा सकता है (देखें तालिका 6)।

तालिका 6 भारतीय पुलिस के आधुनिक हथियारों को शायद कम कर के आंकती हो। गुजरात, जिसके आधार पर ये आंकड़े तैयार किए गए हैं, ने इनसास राइफलों में निवेश करके आधुनिकीकरण किया है (देश गुजरात, 2008); कुछ और राज्यों में भी हथियारों का आधुनिककीरण किया गया, और उनके आधुनिक हथियारों के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। उदाहरण के लिए, यदि छत्तीसगढ़ ने बिना पुराने हथियार बाहर निकाले नए हथियार खरीदकर अपने हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी की तो उस लिहाज़ से देश के हथियारों की कुल संख्या ज्यादा और गुजरात के उदाहरण से आधुनिक होगी।

राज्य और नगरपालिका पुलिस बल पहले सेना के हथियारों पर निर्भर थे, जो सेना में रिप्लेसमेंट के दौरान बाहर किए गए थे। हालांकि हाल के सालों में पुलिस ने आईओएफ से सीधे नए इनसास राइफल और एसएलआर खरीदने शुरू कर दिए थे। 1998 में सेना ने एसएलआर की जगह इनसास राइफलें खरीदनी शुरू की थी, इसलिए लगता है कि एसएलआर बंदूकें ख़ासतौर पर पुलिस, अन्य घरेलू एजेंसियों और निर्यात के लिए बनाई जा रही थीं (कैग, 2010, पृ. 4–5; गंगन, 2011; एमओडी, 2012)।

अर्धसैनिक बलों में छोटे हथियारों की कुल संख्या

भारत के अर्धसैनिक बल उत्तर कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सुरक्षाबल है। ये सशस्त्र घरेलू सुरक्षा एजेंसियां हैं (देखिए तालिका 7) जो देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, अलगाववादी ताक़तों से लड़ती हैं और पुलिस को सेना के स्टाइल में समर्थन देती हैं (शर्मा, 2008, पृ. 3)। इनमें से अधिकांश केन्द्र सरकार के अंतर्गत हैं, और एमरजेंसी की हालत में राज्य सरकारों की मदद करते हैं। मुंबई में 1993 में हुए पहले आतंकवादी हमलों के बाद, और कश्मीर में अलगाववादी हिंसा के शुरू होने का बाद भारत में अर्धसैनिक बलों पर आधुनिकीकरण का दबाव बढ़ गया। आतंकवादियों ने कलाशनिकोव और पिस्तौलों से हमले शुरू कर दिए थे, और आतंकवादियों से ज़ब्त किए गए हथियारों से अंदाज़ा लगने लगा था कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास हथियारों की कितनी कमी थी (कार्था, 1993)।

हथियारों के अधिप्राप्ति के तीसरे चरण के दौरान अर्धसैनिक बल के लिए 1995 में पहली बार कलाशनिकोव राइफल खरीदे गए। इनमें से हुई और खरीद में स्नाइपर राइफलें और सब–मशीनगनों के अलावा भारत में बनी हुई ऑटोमैटिक राइफलें भी शामिल हैं (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2012)। इन अधिप्राप्तियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। अलग–अलग संगठनों के लिए शस्त्रों की अधिप्राप्ति की संख्या अलग–अलग है। जैसे, राष्ट्रीय राइफल्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास सेन्ट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की तुलना में ज्यादा हथियार हैं। यदि भारत में 12 बड़े राष्ट्रीय अर्धसैनिक संगठन हैं, जिनके पास प्रति सुरक्षाकर्मी 1.2 से 1.8 हथियार हैं तो शस्त्रों की कुल संख्या 13 लाख के आस–पास होगी (देखिए तालिका 7)।

भारतीय अर्धसैनिक शस्त्रागारों में ऑटोमैटिक हथियारों की तुलना में पुराने बोल्ट–एक्शन राइफलों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। ये मान लिया जाए कि हथियारों की संख्या का तोड़ मुख्य किस्मों के करीब–करीब बराबर है, और इसके अलावा इनमें दस प्रतिशत पिस्तौलें हैं (स्मॉल आर्म्स सर्वे, 2006, पृ. 56), तो अर्धसैनिक बलों की इन्वेंट्री में तकरीबन 600,000 बोल्ट–एक्शन राइफलें, 550,000 ऑटोमैटिक हथियार, जिनमें राइफलें, सब–मशीनगन और मशीनगन शामिल हैं, के अलावा करीब 100,000 हैंडगन हैं।

भारत में छोटे हथियार

सेना, अर्धसेना और पुलिस के छोटे हथियारों की कुल संख्या का अनुमान तालिका 8 में मिलता है। देश के कुल 560 लाख आधिकारिक हथियारों की अधिप्राप्ति का अनुमान और सेना, अर्धसेना और पुलिस की इन्वेंट्री का अनुमान ऊपर दिया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि भारतीय सेना को 20 लाख नए ऑटोमैटिक राइफलों की आवश्यकता है और सेना, अर्धसेना और पुलिस की ज़रूरतों का अनुमान लगाया जाए तो 40 लाख आधुनिक और नए हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी (बेदी, 2012ए)। जहां सभी तरह के प्रयास टोटल और सब–टोटल संख्याओं को सटीक रखने की कोशिश की गई है, ये अभी भी अनुमान ही हैं जिस पर और शोध और आधिकारिक आंकड़ों की ज़रूरत है।

तालिका 5. गुजरात में पुलिस हथियारों की संख्या. 2009

प्रकार	संख्या	प्रतिशत
.303 राइफल्स	46,357	62
.410 मस्केट्स	8,805	12
हैंडगन और अन्य हथियार	19,415	26
कुल	74,577	100

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

तालिका 6. अनुमानित राष्ट्रीय भारतीय पुलिस हथियार. 2011

प्रकार	विवरण	अनुमानित संख्या
.303 ली–एन्फील्ड	राइफल	1,000,000
.410 मस्कट	शॉटगन	250,000
.38, .45, और 9 मिमी	हैंडगन	300,000
9 मिमी कार्बाइन	सब–मशीन गन	100,000
इनसास, एसएलआर, वगैरह	आधुनिक राइफल	50,000
कुल		1,700,000

स्रोतः हर प्रकार के लिए कुल संख्या इंडियन एक्सप्रेस (2009) से लिए गए अनुपात के आधार पर तैयार की गई। आंकड़ों की गणना एनसीआरबी के राष्ट्रीय पुलिस कर्मचारियों की संख्या के आधार पर की गई। (2012, पृ. 167, 587)।

तालिका 7. भारतीय अर्धसेना में अनुमानित हथियार, 2012

संस्था	कर्मचारी	प्रति व्यक्ति अनुमानित कुल हथियार	अनुमानित कुल हथियार
असम राइफल्स	63,883	1.8	115,000
बीएसएफ	208,422	1.8	375,000
सीआईएसएफ	94,347	1.2	113,000
सीआरपीएफ	229,699	1.2	276,000
डिफेंस सिक्योरिटी कोर	31,000	1.8	56,000
आईटीबीपी	36,324	1.8	65,000
एनएसजी	7,357	1.8	13,000
आरपीएफ	70,000	1.2	84,000
राष्ट्रीय राइफल्स	65,000	1.8	117,000
सहस्र सीमा बल	31,554	1.5	47,000
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स	10,000	1.2	12,000
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप	3,000	1.5	4,500
कुल	850,586		1,300,000

नोटः कुल अनुमानित। अर्धसैनिक संगठनों में डिफेंस और होम गार्ड रिजर्व शामिल नहीं, जो आईआईएसएस द्वारा भारतीय अर्धसैनिक संगठनों में शामिल है। इन दो संगठनों का आकार विवादित है। एनसीआरबी के अनुसार होमगार्ड की सदस्यता 174,958 है (एनसी. आरबी, 2012, पृ. 173)। इन दोनों की कुल ताकत आईआईएसएस में 987,821 बताई जाती है (2012, पृ. 247)। इन्हें बिना हथियारों या हल्के हथियारों के साथ मान लिया गया है। तालिका 7 में राज्यस्तरीय हथियारबंद पुलिस संगठन भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस की बजाय यहां जोड़ा गया है।

स्रोतः कर्मचारियों की संख्या आईआईएसएस से (2012, पृ. 247)। हथियारों के अनुपात लेखक के अनुमान, सुरक्षा एजेंसियों के लोगों से बातचीत, और शर्मा पर आधारित (2008, पृ. 73, 109, 131, 151, 258).

निष्कर्षः एक अनिश्चित दृष्टिकोण

छोटे हथियार कभी बर्बाद नहीं होते, और आमतौर पर फेंके भी नहीं जाते हैं। इसलिए भारत में सुरक्षाकर्मियों का भविष्य बीते दिनों के हथियारों पर निर्भर करता है। उनके पास पुराने हथियार आने वाले कई सालों तक रहेंगे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में नए हथियारों का समावेश धीरे–धीरे ही हो सकता है क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी पुराने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जहां ये ईश्यू ब्रिफ इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक समग्र दृष्टिकोण देने की कोशिश करता है, वहीं आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के छोटे हथियारों के उत्पादन, अधिप्राप्ति और संख्या अभी भी स्पष्ट रूप से आम जानकारी में नहीं है।

बड़ी संख्या में वैसे पुराने हथियार जो और जगहों पर अप्रचलित मान लिए गए हैं, भारत के शस्त्रागारों में सालों तक बने रहेंगे। इस शोध के दौरान भारतीय सेना या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़ी संख्या में छोटे हथियारों के विनाश की कोई घटना सामने देखने में नहीं आई है। पुराने हथियार, जो बदले भी जाते हैं, दूसरी एजेंसियों को सौंप दिए जाते हैं, निकाले नहीं जाते। इससे मालूम पड़ता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अतिरक्त या सरप्लस हथियार रखने की अवधारणा नहीं है।

ली–एन्फील्ड राइफलों जैसे पुराने हथियारों की जगह नए हथियारों को रखने की योजना है। इनमें से सबसे महत्वाकांक्षी योजना भारतीय सेना का एफ–इनसास कार्यक्रम है। इसमें न सिर्फ नए ऑटोमैटिक राइफल्स शामिल हैं, बल्कि सेंसर्स, संचार उपकरण, कपड़े और ऐसे ही कई सेना की ज़रूरतों के सामान हैं (द हिंदू, 2006)। चूंकि इसकी घोषणा 2006 में हुई, लेकिन एफ–इनसास पर काम बहुत धीमी गति से हुआ है। इनसास की जगह नई ऑटोमैटिक राइफलें रखने के लिए बोलियां 43 विदेशी सप्लायरों की ओर से आई थीं। इनमें सभी सुरक्षा एजेंसियों को शामिल कर लिया जाए, तो शायद 60 लाख से ज्यादा छोटे हथियारों की कुल अधिप्राप्ति की ज़रूरत है (बेदी, 2012 बी, पृ. 42)। इस तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल आर्म्स प्रोग्राम यानी छोटे हथियारों की अधिप्राप्ति का कार्यक्रम बन जाएगा।

एफ–इनसास के लिए आउटलुक अनिश्चित है। आईओएफ ने इसके लिए प्रस्ताव आगे रखा है, लेकिन इसके अलावा विदेशी डिज़ाइन और प्रोडक्शन अच्छे विकल्प हो सकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की विकेंद्रित सत्ता हालांकि इस पहल की सुसंगति पर सवालिया निशान छोड़ती है, और ये संभावना दर्शाती है कि भारत सरकार के छोटे हथियार और विविध होने वाले हैं।

इसी तरह, आईओएफ की प्रमुखता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। जहां अन्य भारतीय सैन्य–औद्योगिक क्षेत्रों में निजीकरण किया जा रहा है (मोहंती, 2004, पृ. 34), वहीं घरेलू उत्पादन में एकाधिकार के साथ भारतीय स्मॉल आर्म्स इंडस्ट्री आर्थिक रूप से सुरक्षित है और बिना ये सोचे छोटे हथियार बनाए जा रही है कि आख़िर उनके क्लाइंट्स को उन हथियारों की ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन

तालिका 8. भारतीय अधिकारियों के अनुमानित छोटे हथियार, संगठन और किस्म के आधार पर, 2012

संगठन	.303 राइफल्स	.410 मस्कट्स	आधुनिक राइफल [1]	.मशीनगन	सबमशीनगन	हैंडगन	छोटे हथियारों की अज्ञात किस्म	छोटे हथियार
सेना	305,000	?	1,200,000	?	?	250,000	750,000	2,500,000
अन्यसेना	?	?	?	?	?	?	100,000	100,000
पुलिस	1,000,000	250,000	50,000	?	100,000	300,000	?	1,700,000
अर्धसेना	600,000	?	300,000	50,000	200,000	100,000	?	1,300,000
कुल	1,900,000	250,000	1,550,000	50,000	300,000	650,000	850,000	5,600,000

1 आधुनिक राइफलों में एसएलआर, इनसास राइफलें और अन्य सेमी और पूरी तरह ऑटोमैटिक राइफल शामिल

? का मतलब है, अनुमान के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं

नोटः इस तालिका में सेना और अन्य सेनाओं के कुल में रिजर्व संगठन भी शामिल हैं। ऑफिस के स्टॉक में अज्ञात किस्में भी शामिल, लेकिन उनके किस्मों और संख्या को अलग करके पहचान संभव नहीं। इस तालिका में राष्ट्रीय राइफल्स अर्धसेना में शामिल है, न कि सेना में। राउंड ऑफ करने के बाद कुल संख्या में अंतर संभव।

स्रोतः हर किस्म के लिए सबसे सही अनुपात तालिका4, 6, और 7, और टेक्स्ट के आधार पर लिया गया

जैसे–जैसे विदेशी डिज़ाइनों की उपलब्धता और उन्हें खरीदने की आज़ादी बढ़ती जा रही है, वैसे–वैसे इंडस्ट्री आखरी विकल्प के रूप में सामने आ रही है।

नोट्स

1. भारत में बने हुए छोटे हथियारों की बनावट भ्रामक हो सकती है। ईशापुर राइफल कोई भी वो राइफल होती है, जो ईशापुर में बनी हुई हो; आमतौर पर .303 ली–एन्फील्ड, 7.62 ली–एन्फील्ड, या एसएलआर। भारत के संदर्भ में कार्बाइन का मतलब शॉट राइफल बैरल की जगह सब–मशीनगन होता है (जो कि और संदर्भों में इसका मतलब है)। भारतीय संदर्भ में मस्कट का मतलब शॉटगन होता है।
2. स्टर्लिंग का मतलब स्टेन–गन होता है, हालांकि स्टेन दरअसल एक पुरानी ब्रिटिश सब–मशीनगन है जिसे स्टर्लिंग ने रिप्लेस किया था।
3. भारतीय सुरक्षा कर्मचारियों के साथ इंटरव्यू, नई दिल्ली, सितंबर 2011

बिबलियोग्राफी

ऑल इंडिया, 2012. 'ओवर 29,000 एके–47 प्रोक्योर्ड फॉर इंडियाज़ पैरामिलिट्री फोर्स,' 20 मई

बैडले, एडम. 2012 'इन्फेंट्री वेपन्स एंड साइट्स'। एशियन मिलिट्री रिव्यू, वॉल्यूम 20, नंबर 4. जुलाई–अगस्त, पृ. 24–29

बेदी, राहुल. 1999. 'मिक्स्ड फॉर्च्युन्स फॉर इंडियाज़ डिफेंस इंडस्ट्रियल रेवेल्युशन.' जेन्स इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू, नंबर 5, मई, पृ. 22–29

– 2012ए. 'आर्म्स ट्विस्टेड.' तहलका, वॉल्युम 9, नंबर 17. 28 अप्रैल

– 2012बी. 'इंडिया: मैसिव मॉर्डनाइज़ेशन बट पूअर प्रोक्योरमेंट'. एशियन मिलिट्री रिव्यू, वॉल्यूम 20, नंबर 2, अप्रैल–मई, पृ. 36–42

बीपीआरडी (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट). 2010. इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ मॉर्डनाइज़ेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस (एमपीएफ). नई दिल्ली: बीपीआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया. http%//mha-nic-in/pdfs/FR&ImpactAssessment&BPR&d-pdf

बन्कॉम्ब, एंड्रयु. 2011. 'यूएस फोर्स्ड टू इम्पोर्ट बुलेट्स फ्रॉम इज़रायल एज़ ट्रूप्स यूज़ 250,000 फॉर एवरी रेबल किल्ड.' बेलफास्ट टेलीग्राफ. 10 जनवरी.

कैग (कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया). 1995. 'चैप्टर प्टः ऑर्डनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइज़ेशन.' नई दिल्ली. http%//www-cag-gov-in/reports/defence/1995_book2/chapter4-htm

– 2001. 'चैप्टर टप्: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइज़ेशन.' नई दिल्ली. http%//www-cag-gov-in/reports/defence/2001_book2/

– 2010. कॉम्पेन्डियम ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट रिव्यूज़ ऑन मॉर्डनाइज़ेशन ऑफ पुलिस फोर्स. <http%//www-cag-gov-in/html/Compendium_MPF/MPF-pdf>

कोहेन, स्टीफेन एंड सुनील दासगुप्ता. 2010. आर्मिंग विदाउट एमिंग: इंडियाज़ मिलिट्री मॉर्डनाइज़ेशन. वाशिंगटन, डी.सी.: ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन

कटशॉ चार्ल्स. 2006. टैक्टिकल स्मॉल आर्म्स ऑफ द सेवेंटी फर्स्ट सेंचुरी: अ कम्पलीट गाइड टू स्मॉल आर्म्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. आयोला, विस्कॉन्सिन: गन डाइजेस्ट बुक्स.

देश गुजरात (अहमदाबाद). 2008. 'गुजरात पुलिस टू गेट इनसास राइफल्स टू फाईट अगेन्स्ट टेरर.' 4 नवंबर.

डीआईडी (डिफेंस इंडस्ट्री डेली). 2007. 'टैवोर–21 राइफल हेडेड इनटू सर्विस विथ इंडियन स्पेशल फोर्सेस. 28 फरवरी. <http%//www-defence-industrydaily-com/tavor21&rifle&headed&into&service&with&indian&special&forces&03080/>

ईगर, क्रिस्टोफर. 2006. 'प्रोडक्शन वेरिएन्ट्स ऑफ द एफएएलः द एफएन एफएएल एंड द एल1ए1 एसएलआर राइफल्स एंड देयर यूज़र्स.' सूट 101. 30 दिसंबर.

अर्न्स्ट एंड यंग. 2010. असेस्टमेंट रिपोर्टः इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द मॉर्डनाइज़ेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम 2000–02 टू 2008–09. नई दिल्ली: अर्न्स्ट एंड यंग.

एज़ेल, एडर्वड. 1988. स्मॉल आर्म्स टुडेः लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऑन द वर्ल्ड्स वेपंस एंड एम्युनिशन्स, सेकेंड एडिशन. हैरिसबर्गः स्टैकपोल

– 2001. कलाशनिकोवः द आर्म्स एंड द मैन, रिवाइज़्ड एडिशन. ऑन्टारियोः कलक्टर ग्रेड पब्लिकेशन्स

फोरकास्ट (ऑर्डनेंस एंड म्युनिशन्स फोरकास्ट).

2012. 'मिलिट्री राइफल्स (इंटरनेशनल)'. न्यूटाउन, कनेक्टीकटः फोरकास्ट असोसिएट्स

गंगन, सुरेन्द्र. 2011. 'महाराष्ट्र पुलिस टू गेट 2के बुले. टप्रूफ जैकेट्स, 10के राइफल्सः आरआर पाटिल.' डीएनए इंडिया. 28 जुलाई.

ग्राहम, थॉमस. 1984. 'इंडिया.' इन जेम्स एवरेट काट्ज़. एड. आर्म्स प्रोडक्शन इन ड्वलपिंग कंट्रीज़: एन एनालिसिस ऑफ डिसिज़न मेकिंग. लेक्सिंगटन, मैसाच्युसेट्सः लेक्सिंगटन बुक्स.

गुप्ता, अमित. 1990. 'द इंडियन आर्म्स इंडस्ट्रीः ए लंबरिंग जाएंट?' एशियन सर्वे, वॉल्यूम 30, नंबर 9. सितंबर, पृ. 846–61.

गुरुस्वामी, मोहन. 2006. इंडियाज़ वर्ल्डः एसेज़ ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़. गुड़गांवः होप इंडिया.

गाय, एलेन, पीटर ब्रॉयन, एंड मैरियन हार्डिंग, एड. 1997. सोल्जर्स ऑफ द राजः द इंडियन आर्मी 1600–1947. लंदनः नेशनल आर्मी म्यूज़ियम

द हिंदू (नई दिल्ली). 2006. 'हाई टेक सिस्टम टू प्रोवाइड इंडियन सोल्जर विथ ओवरमैच फैसिलिटिज़'. 9 मई.

– 2008. 'एंटी–मैटीरियल राइफल हैंडेड ओवर टू बीएसएफ.' 15 फरवरी.

इंडिया टुडे. 2013. 'जम्मू: राष्ट्रीय राइफल्स जवान किल्स कॉलीग विथ हिज़ एके 47 ड्यू टू एन ऑल्टरकेशन.' 28 मई.

इंडियन एक्सप्रेस. 2009. 'कैग रिपोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट आईआईएसएस (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़).' 2000. द मिलिट्री बैलेंस 2000–2001. ऑक्सफोर्ड एंड लंदनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड आईआईएसएस.

– 2010. द मिलिट्री बैलेंस 2012. एबिंग्डन एंड लंदनः रूटलेज एंड आईआईएसएस

आईओबी (इंडियन ऑर्डनेंस बॉड) एन.डी.ए. ब्रिफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्डनंस फैक्ट्री कानपुर. कानपुरः आईओबी.

– एन.डी.बी. ऑर्डनंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली. तिरुचिरापल्लीः आईओबी

कार्प, एरन. 2013ए. डेटा सॉसेस एंड द एस्टीमेशन ऑफ मिलिट्री–ओन्ड स्मॉल आर्म्स.

रिसर्च नोट 34. जिनीवाः स्मॉल आर्म्स सर्वे

– 2013बी. लेगेसिज़ ऑफ वॉर इन द कंपनी ऑफ पीसः फायरआर्म्स इन नेपाल. नेपाल आर्म्ड वायलेंस असेसमेंट ईश्यू ब्रिफ 2. जिनीवा एंड काठमांडूः स्मॉल आर्म्स सर्वे

कार्था, तारा. 1993. 'द स्प्रेड ऑफ आर्म्स एंड इनस्टेबिलिटी'. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, वॉल्यूम 16, नंबर 8, पृ. 1033–50

काविक, लॉर्न. 1967. इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटीः डिफेंस पॉलिटिक्स 1947–1965. बर्कलेः यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.

खन्ना, अमन. 2004. 'असॉल्ट राइफल्स हिट होम.' तहलका, 3 मार्च

लैडलर, पीटर एंड डेविड हॉउरॉयड. 1995. द गन्स ऑफ डैगेनहैम. कोबर्ग, ऑन्टारियोः कलक्टर ग्रेड पब्लिकेशन्स

लॉन्ग, डंकन. 1998. द एफ–एफएएल राइफल, एट ऑल. कॉर्नविल, अर्कान्सासः डेज़र्ट पब्लिकेशन्स.

मारवाह, सोनल. 2010. डायगोनॉजिंग परसेप्शन्स ऑफ सिविलियन सिक्योरिटीः द डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन डिमांड फॉर स्मॉल आर्म्स इन डेल्ही. मास्टर्स थीसिस, जिनीवाः ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़.

मेंगल, डीन एंड विलियम ब्रॉन. 2005. अम्युनिशन्स शॉर्टेजेज़ एक्सपीरियंस्ड इन ऑपरेशन एन्ड्युरिंग इराकी फ्रीडमः कॉजेज़ एंड सॉल्युशन्स. कार्लिसले, पेनसिल्वेनियाः यूएस आर्मी वॉर कॉलेज.

एमजीए (मिलिट्री गन्स ऑस्ट्रेलिया). एन.डी. 'ईशापुर 2ए–2ए1, द लास्ट ली एन्फील्डः' http%//fire-arms-net-au/military/content/view/83/147/

एमओडी (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया): 2012. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल वेपन्स. न्यू डेल्ही: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. 21 मई. http%//pib-nic-in/newsite/erelease-aspx\relid=84268

मोहंती, देबा. 2004. चेंजिंग टाइम्स? इंडियाज़ डिफेंस इंडस्ट्री इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी. पेपर 36. ब्रॉनः बॉन इंटरनेशनल कन्वर्ज़न सेंटर. http%//www-bicc-de/uploads/tx_bicctolls/paper36-pdf

मुंबई मिरर. 2012. 'इट्स लाठीज़ वर्सेस गन्स इन छत्. तीसगढ़'. 12 अप्रैल, पृ. 12.

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो). 2012. क्राइम इन इंडिया 2011: स्टैटिस्टिक्स. न्यू डेल्ही: एनसीआरबी.

ओएफबी (ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड). 1999. 'हिस्ट्री. राइफल फैक्ट्री ईशापुर.' ओएफबी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस.

– 2005. ऑर्डनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली. ओएफबी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस

– एन.डी.ए. एंटी मैटिरियल राइफल विध्वंसक

एन.डी.बी. जटिरा मल्टी–परपज़ कार्बाइन, कोलकाताः ओएफबी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस

पेज, जेरेमी. 2008. 'आउटगन्ड मुंबई पुलिस हैंपर्ड बाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेपन्स.' द टाइम्स (लंदन), 3

दिसंबर.

प्रधान, आर.डी. 1998. डिबैकल टू रिवाईवलः वाई.बी. चव्हाण ऐज़ डिफेंस मिनिस्टर, 1962–1965. नई दिल्लीः ओरियंट लॉन्गमैन

राघवन, आर. के. 1993. 'इंडिया इन वर्ल्ड फैक्ट–बुक ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स. वॉशिंगटन डीसी.: यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस.* http%//www-ncjrs-gov/pdffiles1/Digitization/169644NCJRS-pdf

राघवन, रंजनी एंड ओईनम आनंद. 2009. 'सिटी इंस्टीट्यूट रेडी विद न्यू गन फॉर आर्मी.' इंडियन एक्सप्रेस. 21 अगस्त.

राज्यसभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया). 1997. 'सप्लाई ऑफ लो क्वालिटी राइफल्स टू फाइट अगेन्स्ट इनसर्जेंसी इन नॉर्थ–ईस्ट रीजन.' सेशन नं. 180 (पार्ट 1) अनस्टार्ड क्वेशचन नं. 2607. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 19 मार्च. <http%//rsdebate-nic-in/handle/12345678/142578>

– 2000ए. 'सप्लाई ऑफ राइफल्स टू आर्म्स फोर्सेस.' सेशन नं. 190 (पार्ट 1) अनस्टार्ड क्वेशचन नं. 326. 26 जुलाई. <http%//rsdebate-nic-in/handle/12345678/5405>

– 2000ए. 'पर्चेस ऑफ एके राइफल्स.' सेशन नं. 190 (पार्ट 1) अनस्टार्ड क्वेशचन नं. 2492. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 16 अगस्त. <http%//rsdebate-nic-in/handle/12345678/3894>

– 2005. 'वेपन्स फ्रॉम इज़रायल.' सेशन नं. 205 (पार्ट 1). अनस्टार्ड क्वेशचन नं. 1790 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 10 अगस्त. http%//rsdebate-nic-in/handle/123456789/57499

– 2009. 'केपैसिटी ऑफ डिफेंस फैक्ट्रीज़.' एने. क्सचर–1, स्टेटमेंट इन पार्ट (ए) ऑफ अनस्टार्ड क्वेशचन नं. 2966. 16 दिसंबर. http%//164-100-47-5%8080/members/Website/quest-asp\qref=149232

– 2010. 'स्टेटमेंट इन रिप्लाई टू पार्ट्स (ए) टू (ई) ऑफ राज्यसभा स्टार्ड क्वेशचन नं. 93 फॉर 03.03.2010 रिगार्डिंग (स्ट्रेन्देनिंग पुलिस फोर्सेस इन स्टेट्स).' मल्लापल्ली रामचंद्रन. मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. http%//164-100-47-5%8080/members/Website/quest-asp\qref=151428>

रॉबर्ट्स, ग्रेग. 2011. 'फुल ऑटो चेक सीज़ी–75 मिमी ऑटोमैट.' कॉम्बैट एंड सर्वाइवल, सितंबर, पृ. 36–40.

रॉय, कौशिक. 2003. 'इक्विपिंग लेवियाथनः ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज़ ऑफ ब्रिटिश इंडिया. वॉर इन हिस्ट्री, वॉल्युम 10, नंबर 4–अक्टूबर, पृ. 398–423.

शर्मा, एम.सी. 2008. पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, नई दिल्लीः कल्पाज़ पब्लिकेशन्स.

सिद्दिकी, इमरान. 2009. '...फॉर आवर कॉप्स विथ मस्कटस'. द टेलीग्राफ (कोलकाता). 27 नवंबर.

सिन्हा, शिशर. 2012. 'स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप मॉर्डनाइज़ेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस.' द हिंदू (नई दिल्ली) 16 अप्रैल.

स्केनेर्टन, आएन. 1993. ली–एन्फील्ड स्टोरी. बैंकॉकः थाई वॉटना पैनिक प्रेस.

स्मॉल आर्म्स सर्वे. 2006. स्मॉल आर्म्स सर्वे 2006ः अनफिनिश्ड बिज़नेस. ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

स्मिथ, क्रिस. 1994. इंडियाज़ ऐड हॉक आर्सेनल. ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

स्वामी, प्रवीण. 2009. 'नौ बैंग इन मुंबई पुलिसेज़ न्यू गन्स'. द हिंदू. 8 अप्रैल.

थायर, जॉर्ज. 1969. द वॉर बिज़नेसः द इंटरनैशनल ट्रेड इन आर्मामेंट्स. न्यूयॉर्कः साइमन एंड शूस्टर.

थॉमस, राजू. 1978. द डिफेंस ऑफ इंडियाः ए बजटरी पर्स्पेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजी एंड पॉलिटिक्स. न्यू डेल्हीः मैकमिलन.

थॉमसन, लेरॉय. 2012. द स्टेन गन. ऑक्सफोर्डः ऑस्प्रे.

टीओआई (टाइम्स ऑफ इंडिया). 2011. 'तिरुची ऑर्डनेंस फैक्ट्री डेवलप्स न्यू असॉल्ट राईफल'. 19 मार्च.

– 2012. 'गवर्नमेंट प्रॉमिसेस टू इक्विप पुलिस विथ लेटेस्ट वेपन्स फायरआर्म्स.' 3 जुलाई.

उन्नीथन, संदीप. 2011. 'फोर्सेस फेस गन क्राइसिस.' इंडिया टुडे, 7 मई.

वॉलपोनी, पाओलो. 2009. 'देअर आर टू टाईप्स ऑफ मेन इन दिस वर्ल्ड... 'अर्मादा इंटरनेशनल, जून. http%//www-webcitation-org/5nWZloBMW

वॉल्टर, जॉन. 2005. गन्स ऑफ द गुरखाज़ः द लॉस्ट आर्सेनलः पिस्टॉल्स, राइफल्स एंड मशीनगंस ऑफ द रॉयल नेपलीज़ आर्मी, 1816–1945. गॉडस्टोनः थार्स्टन प्रेस.

यूसफ़, मोहम्मद एंड मार्क एडकिन. 1992. द बेयर ट्रैपः अफगानिस्तांस अनटोल्ड स्टोरी. लंदनः लिओ कूपर.

भारतीय सशस्त्र हिंसा आकलन के विषय में

भारतीय सशस्त्र हिंसा आकलन (इंडियन आर्म्ड वायलेंस असेसमेंट या IAVA) रिसर्च को बढ़ावा देता है और सशस्त्र हिंसा के कारणों और निष्कर्षों को समर्पित भारतीय समाज–शास्त्र शोध समुदायों को शोध के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार किया गया ये समूह सुरक्षा के विभिन्न कारकों, हिस्सेदारों और सक्षम संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की खोज करता है। आईएवीए का मकसद भारत में इन मुद्दों पर साक्ष्य–आधारित बहस छेड़ना और वैश्विक नीतियों और कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान को आगे बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट को स्मॉल आर्म्स सर्वे का समर्थन प्राप्त है।

आईएवीए के विषय विवरण या इश्यू ब्रीफ सशस्त्र हिंसा से जुड़े मुख्य प्रसंगों पर जानकारियों की स्थिति का जायजा लेते हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे द्वारा कमीशन किए गए ये विषय विवरण संघर्ष और अपराध से जुड़ी हिंसा, अपराध करनेवालों और अपराध के शिकार लोगों के विषय में, किसी खास किस्म की हिंसा को रोकने और कम करने के लिए रणनीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार हैं। इन्हें तैयार करते हुए सशस्त्र हिंसा के पैमाने और रूपों तथा उसकी उग्रता, उसके कारणों और जवाबी नीतियों के प्रभाव से जुड़े शोध पर ध्यान दिया जाता है, और ये शोध आंकड़ों पर आधारित होते हैं।

आईएवीए विषय विवरण अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। इन्हें www.smallarmssurveyindia.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी प्रिंट कॉपियां स्मॉल आर्म्स सर्वे से प्राप्त की जा सकती हैं।

क्रेडिट

लेखक: ऐरॉन कार्प और राजेश राजगोपालन

अनुवादक: अनु सिंह

प्रूफरीडर: उर्मिला गुप्ता

डिजाईन एंड लेआउट: रक जोन्स, डिजाइन एक्जाइल (rick@studioexile.com)

संपर्क का पता

सोनल मारवाह, प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेटर: sonal.marwah@smallarmssurvey.org

ऐरॉन कार्प, आईएवीए सीनियर कन्सल्टेंट: akarp@odu.edu

स्मॉल आर्म्स सर्वे

47 एवेन्यू ब्लॉ 1202 जिनिवा स्विटजरलैंड

टेलीफोन 41 22 9085777
फैक्स 41 22 7322738

India
Armed Violence Assessment
A project of the Small Arms Survey

small arms survey